

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, जिस सवाल को आज सदन में आपके आने के साथ ही उठाने का प्रयास हुआ था, वह अकाल का मामला था। देश में जिस तरह के हालात हैं, हमने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा उलट-फेर नहीं देखा है। बिहार ऐसी जगह है, जिसे पानी का सूबा कह सकते हैं। पूरा देश का, खासकर के हिमालय की तराई से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के सभी भागों में, मैं उतनी पक्की जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इस सदन के सदस्यों से ज्यादा मेरी राय में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस देश की धरती और जमीन को जानता हो। यह इतना गंभीर संकट है कि सदन के चलते यदि हमने इसका रास्ता या रोडमैप नहीं बनाया फिर आगे आने वाले देश में जो संकट है, उस चुनौती से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देश में पानी की स्थिति जिस तरह बिगड़ी है, यहां प्रणब बाबू बैठे हैं। इन्द्र देवता को मैं नहीं मानता कि इन्द्र देवता पहले भी और बाद में भी, मैं मानता हूँ कि धरती और चराचर पर्यावरण से चलता है। आज नदियां सूख रही हैं, गंगा की धारा भी बीस-बीस मीटर खिसक रही है। नर्मदा नदी में सदा पानी रहता था, जो सूख रही है, चम्बल में जितने घड़ियाल हैं, अकेले उनका जीवन संकट में नहीं है, नदियां पूरी की पूरी सूख रही हैं, जिनमें सदा पानी रहता था। भाखड़ा नांगल देश का सबसे बड़ा जलाशय है, उसमें संकट है। पूरे देश के कई शहरों में पीने के पानी का हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पानी का संकट है। यहां बिजली मंत्री नहीं हैं, दो-तीन मंत्री राज्य सरकारों के आए थे। वे हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने बताया कि पानी से जो बिजली बनती है, उसके जेनरेशन में बहुत बड़े पैमाने पर कमी हो गई। बिजली एवं पीने के पानी का संकट होगा। जो वसुन्धरा अनाज देती है, इस देश में 75 फीसदी जमीन बरसात पर चलती है। ऐसी विकट परिस्थिति है, हम सब सदन में बैठे हैं। आप इस सदन की मालिक हैं और हम लोग सारी चिन्ताएं आपके तहत उठाते हैं। इससे विकट स्थिति कभी देश के सामने नहीं थी।

हमने इन सारी चीजों पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए। हमने सचिवों की बैठक की है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि इस सवाल पर, जो एक रूटीन रास्ते से हम चलते आए हैं, उससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। हम जब तक देश भर के लोगों को पूरी तरह इस बहस में, फैसले में हर तरह से उन्हें शामिल करने का काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। यहां सदन के नेता प्रणब बाबू जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करूंगा। आपकी मिनिस्ट्री में बहस हुई है, आपके सचिवों ने बहुत मीटिंगें की हैं, राज्य और सूबों से आपके पास सूचनाएं आ गई हैं, ठीक है। इस देश में सब पार्टियों की सरकारें हैं।

अध्यक्ष महोदया, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, बजट की बहुत कमी है, लेकिन सभी राज्य सरकारों के जो मंत्री एवं विधायक हैं, वे जितना देश को जमीन पर जानते हैं, उनसे ज्यादा जमीन को जानने वाले लोग कितनी भी बात करें, लेकिन इस सदन के लोग देश के चप्पे-चप्पे की खबर दे सकते हैं। तत्काल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को बुला कर बात करें। मौसम की क्या हालत है, कहां पानी बरसा और कहां नहीं बरसा है। स्वामी नाथन जी इस देश के बहुत बड़े जानकार कृषि विशेषज्ञ हैं। मैं मानता हूँ कि वे खेती और फसल के बहुत बड़े जानकार हैं। उनका तीन दिन पहले हिन्दू अखबार में सुझाव आया, बहुत जगह पानी बरसा है, कई सूबों में बीज बोने लायक पानी बरसा है। हमें तत्काल सारे मुख्यमंत्रियों को बुला कर इस बारे में बात करनी चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा अन्य भी देश के बहुत सारे इलाके हैं, बहुत से सूबे हैं, जहां पानी बरसा है।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पूरे देश में सुखाड़ की स्थिति है।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : सुखाड़ है, लेकिन कई जगह पानी बरसा है।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बिहार पानी का सूबा है, वहां भी अकाल की स्थिति है।

महोदया, पूरा मगध कई वर्ष से सूखे की चपेट में है। बुन्देलखंड तो वर्षों से, एक वर्ष से नहीं, बल्कि सात-आठ वर्षों से सूखे की चपेट में है और पूरी तरह से उजाड़ हो गया है। पशु मर गए हैं और पक्षी उड़ गए हैं। विकट परिस्थितियां हैं। चारे की दिक्कत होगी। पानी की दिक्कत होगी और पूरे देश के जो पशु-पक्षी हैं, वे भी मर-मर कर गिर रहे हैं। हमारी खेती और किसानों में जो सबसे ज्यादा मददगार हैं, वे जानवर भी तबाही और दिक्कत के दौर में हैं। मैंने आपसे कहा कि डॉ. स्वामीनाथन जी ने कुछ दिन पहले ही कुछ सुझाव दिए हैं। मैं आपके माध्यम से श्री प्रणब मुखर्जी से कहना चाहता हूँ कि तत्काल देश के प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएं, तत्काल सारी पार्टियों को बुलाएं और बैठक करें तथा देखें कि देश में कहां-कहां पानी गिरा है और कहां-कहां हम फसल को ठीक प्रकार से और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। राजस्थान है, पंजाब है और वैस्टर्न यू.पी. है, वहां तो कोई फसल होने वाली नहीं है। जहां फसल हो सकती है, वहां हमें तत्काल हाथ डालना चाहिए और सब तरह की सामर्थ्य और शक्ति लेकर हमें वहां जाना चाहिए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह काम आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से दिल्ली में बैठकर होने वाला नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि वे लोग काबिल नहीं हैं। वे बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन आपको देश के बारे में यहां बैठकर बहुत सी जानकारी नहीं मिल पाती है। बहुत सी चीजों के बारे में वहां के जो लोग बता पाएंगे, वे यहां बैठकर नहीं जानी जा सकती हैं। देश ऊपर से भी चलाया जाएगा और नीचे से भी चलाया जाएगा। यह ऐसा संकट है जिसके इंतजाम के लिए आपको तत्काल कदम उठाने चाहिए और अगर आपने तत्काल कदम नहीं उठाए, तो जो आपका बजट है, वह 'ऊंट के मुंह में जीरा' साबित होगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो संकट आने वाला है, उसमें आप टिकने वाले नहीं हैं और यह ऐसा संकट होगा, जिसमें हर तरह की कठिनाई होगी। इसमें प्यास, भूख, जानवर, जंगल, धरती, आकाश और गर्मी का सभी तरह का संकट होगा। इस तरह से तबाही होगी जो हमने कभी देखी भी नहीं होगी। इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी, जो सदन के नेता हैं, मैं पार्टी के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं मन से जरूर बेचैन हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जिस शिद्दत से आपको पहल करनी चाहिए, वह तत्काल करें और सारे मुख्य मंत्रियों को बुलाएं और दो दिन बैठकर, हिन्दुस्तान के सामने जो सूखे का संकट है, जो चुनौती है, उससे कैसे निपटें, इस बारे में सारे कदम उठाने का काम करें।

महोदया, आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री गोपीनाथ मुंडे।

â€(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी आप बैठ जाइए।

â€(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जो श्री गोपीनाथ मुंडे बोल रहे हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड पर जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। देश में इस समय कृषि विभाग ने मानसून के जो अंदाजे प्रकट किए थे, वे सारे गलत निकले। विभाग ने जो अनुमान लगाया था, उससे ऐसा प्रकट होता था कि इस वर्ष देश में अच्छा मानसून होगा, लेकिन वह सत्य नहीं निकला। आज पूरे देश में अकाल की स्थिति है। देश में वर्ष 1972 के बाद यह सबसे बड़ा अकाल है। अकाल के कारण देश की स्थिति बहुत गम्भीर बन चुकी है। एक प्रदेश नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में आज अकाल की स्थिति है। आज यहां हमारे सदन के नेता भी बैठे हैं। अगर देश की स्थिति की गम्भीरता को ठीक प्रकार से पार्लियामेंट नहीं समझेगी और उपाय नहीं करेगी, तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। इतने बड़े संकट से मुकाबला करने के लिए प्रदेशों के पास साधन नहीं हैं, उनके पास धन नहीं है। वे इस अकाल की स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज किसान की स्थिति ठीक नहीं है। वे जानवरों को बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पीने के पानी का संकट तो इतना गम्भीर है कि आज लोगों को गांवों में पीने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। सूखे के कारण देश की स्थिति बहुत गम्भीर बन चुकी है। इसलिए उनके लिए पानी तथा रोजगार के तत्काल उपाय करने चाहिए।

महोदया, सूखे के कारण महाराष्ट्र की स्थिति भी बहुत खराब है। आज वहां बरसात के दिनों में भी 7500 गांवों में टैंकों से पानी दिया जा रहा है। देश के जितने भी बड़े डैम हैं, उनमें 10 प्रतिशत भी पानी नहीं है, जबकि जुलाई का महीना आधा समाप्त होने जा रहा है। यह नैचुरल कैलेमिटी है। यह नैसर्गिक आपदा है। पहले इसकी जांच की जानी चाहिए कि विभाग द्वारा मानसून का जो अंदाज लगाया गया, वह गलत कैसे साबित हुआ। जिन किसानों ने सोइंग की थी, बरसात नहीं होने के कारण वह बुवाई बेकार हो गई और अब यदि बरसात होगी, तो उन्हें दुबारा बुवाई करनी पड़ेगी।

उसका खर्चा करने के लिए किसान को जमीन बेचनी पड़ेगी, नहीं तो पत्नी के गहने बेचने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। देश में किसानों को सोइंग करने के लिए भी अनुदान देना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी। केन्द्र सरकार यहां बैठकर क्या करेगी, प्रदेशों में चूंकि यह राज्यों पर छोड़ देगी तो मेरी मांग है कि जिन प्रदेशों में अकाल है, उन प्रदेशों में आप सैण्टर की टीम भेज दें। यह बजट सेशन चल रहा है, इसलिए नैचुरल कैलेमिटी में मदद करने के लिए एक अलग राशि निकाली जाये और उससे प्रदेशों की मदद की जाये। अगर प्रदेश केन्द्र पर और केन्द्र प्रदेश पर छोड़ देगा तो बहुत बड़ा संकट होने वाला है।

एक और बहुत गहरा संकट आया है कि लोग रोजगार के लिए शहरों में स्थानान्तरित हो रहे हैं। लोग रोजगार के लिए गांव छोड़कर जा रहे हैं, इस स्थानान्तरण को रोकना चाहिए। इस देश में अकाल के बाद अगर उनके पास पीने का पानी नहीं है, जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं है तो गांवों में ही उनको रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। यह जिम्मेदारी केन्द्र टाल नहीं सकता। हमारे कृषि मंत्री परिस्थिति इतनी गम्भीर होने के बाद भी कहते हैं कि मानसून अच्छा होगा, बरसात गिरेगी। यह भविष्य में कौन कह सकता है। आज स्थिति गम्भीर है और इससे निपटने के लिए, इस स्थिति में गरीब लोगों को राहत देने के लिए केन्द्र को कड़े कदम उठाने चाहिए और कुछ घोषणाएं करनी चाहिए और अपने बजट में से कुछ अलग राशि निश्चित रूप से देनी चाहिए।

आज अनाज की देश में कमी नहीं है, आप लोगों ने चुनाव में प्रचार किया कि अनाज के गोदाम भरे हुए हैं, जबकि गोदाम खाली हैं। अगर संकट आएगा तो अनाज भी नहीं मिलेगा, इसलिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी पॉलिसी तय करनी चाहिए। हमारे देश का

अनाज अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बड़ा खतरा मोल लेंगे। कुछ चीजें हैं, जो इस देश के लिए आपको आज से मंगानी होंगी, चूंकि यह अकाल साल भर रहेगा। इसके लिए शॉर्ट टर्म कई मैजर्स उठाने पड़ेंगे और लॉंग टर्म मैजर्स उठाने पड़ेंगे।

जैसे बुन्देलखंड की एक बात की, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मराठवाड़ा और विदर्भ हैं, वहां हमेशा अकाल आता है। उन क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए कि आगे अकाल न हो और जितना उपलब्ध पानी है, उसको अपने प्रदेश, अपने डैम पूरा नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। जैसे हमारी एन.डी.ए. सरकार ने गंगा-कावेरी जोड़ने का प्रयास किया था, अगर आप उस प्रोजेक्ट को पांच साल में पूरा करते तो शायद अकाल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हमारी सरकार गंगा-कावेरी को जोड़ने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये देती और वह प्रकल्प आज पूरा होता तो आज हमें अकाल का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बारे में अभी भी देर नहीं हुई है। अकाल का तो सामना करना पड़ेगा, अकाल के लिए तो राशि उपलब्ध करानी पड़ेगी, लेकिन गंगा-कावेरी के लिए आज भी देरी नहीं हुई है, आप इसमें शुरुआत करो। गंगा में भी पानी नहीं है, आज यह कहा जा रहा है। जब सरकार इसके बारे में नहीं सोचेगी तो इस देश को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और इससे गांव, गरीब और किसानों को नुकसान होगा।

मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सदन के नेता और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। आपने आर्थिक मंदी के लिए पैसा दिया, उसके लिए पैकेज दिया तो गांव, गरीब और किसानों के लिए पैकेज क्यों नहीं उपलब्ध सूखे में करा रहे हैं, उसकी मदद के लिए सरकार क्यों नहीं आगे आती? क्योंकि, वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते, वे आप तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए गांवों के लोगों को, जानवरों को बचाने का काम सरकार को करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिये।

श्री गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, इस पर सदन में बहस होनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आपको धन्यवाद। आपने सूखे के सवाल को गम्भीरता से लिया। हम उन बातों को नहीं दोहराना चाहते, माननीय शरद यादव जी ने कहा है, मुंडे साहब ने भी कहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सूखा तो पड़ा ही है और सूखा ऐसा है, जो लगभग पूरे देश में है। उत्तर भारत पूरी तरह सूखे की चपेट में है। सबसे ज्यादा उत्तर भारत है और अन्य भी प्रदेश हैं।

आज सवाल है कि पानी तो है नहीं, तालाब, गड्ढे जो भी हुआ करते थे, वे भी खत्म हो गये। अब तो तालाबों को पाटकर जमीन बना ली गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश भी दिया कि जितने पुराने तालाब थे, उन तालाबों को खुदवाया जाये, उन पर से कब्जे हटाये जायें। जो गड्ढे तालाब हुआ करते थे, वे जानवरों को पानी पीने के अलावा और जो जलस्तर नीचे जाता था, उसको रोकने के लिए ऐसे मौके पर मदद करते थे। जल स्तर नीचे चला गया है, ट्यूबवेल में पानी नहीं है, हैंड पंप कामयाब नहीं हैं। आज इस तरह की परेशानियां हैं कि न पीने के लिए पानी है, न जानवर के लिए, न इन्सान के लिए है। आज यह हालत है।

दूमरी चीज, आगे सबसे बड़ा संकट अन्न का आने वाला है। यह फसल तो गयी, खरीफ की फसल में कुछ पैदा नहीं होना है और आगे आने वाली रबी की फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला सवाल जहां पानी का है, वहां अन्न का भी साथ-साथ संकट होगा। इससे भुखमरी फैलेगी, जब भुखमरी फैलेगी तथा पानी नहीं मिलेगा, तो फिर लोग लूट करेंगे, डंडा चलेगा, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, झपटमारी होगी कि पानी कहाँ है और खाने का अन्न कहाँ है? यह हालत देश के अंदर आने वाले समय में होगी। कोई इन्सान भूखा नहीं मरना चाहेगा कि दूसरा खाये और वह भूखा रहे, लोगों में छिनाझपटी होगी। माननीय नेता सदन बैठे हैं, वह इसे गंभीरता से लें और सारे नेताओं की बैठक बुलायें। आप अकाल घोषित करें और तत्काल चारे का इंतजाम करें। जहां गरीब भूखों मरने वाले हैं, मर रहे हैं, मजदूर हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए तत्काल खाने-पीने का इंतजाम भी करें।

अध्यक्ष महोदया, सवाल यह है कि आज जल स्तर भी नीचे गया, जो सबसे बड़ा संकट है। गंगा को हम क्यों पूजते हैं, क्योंकि यह अन्न खिलाती है, इसलिए गंगा का इतना महत्व है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ गयी है कि बीस-पच्चीस साल बाद गंगा में पानी नहीं होगा। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ चुकी है, ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं कि सरकार ने इसे कितनी गंभीरता से लिया है कि गंगा सूखने वाली है और गंगा के सूखने के बाद क्या हाल होगा? सब जगह रेगिस्तान हो जाएगा। जहां असली पैदावार होती है, गंगा-जमुना के मैदान को जिसे सबसे ज्यादा उर्वरा माना जाता है, जो अन्न देता है, वह रेगिस्तान हो जाएगा।

वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है, जो चर्चायें हैं, अखबारों में हैं, मैगजीन में हैं, उस के बारे में सरकार ने क्या विचार किया है कि जब गंगा सूखेगी तो देश का क्या हाल होगा? आप समझ लीजिए कि फिर तो पूरा देश रेगिस्तान हो जाएगा। यह गंभीर स्थिति सूखे तक ही सीमित नहीं है। सूखे के साथ-साथ ये सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। नदियां सारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गंगा का इतना महत्व है कि गंगा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। गंगा ही तो सबसे ज्यादा अन्न पैदा कर रही है। यहां से लेकर आप कलकत्ता तक चले जाइए, पूरे इलाके में वह अन्न पैदा कर रही है। आज वहां सूखे का सवाल है। इसके साथ जो तालाब और गड्ढे हैं, उनमें पानी नहीं है, जानवरों के पीने के लिए नहीं है। जल स्तर नीचे जा रहा है, ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं और हैंडपंप काम नहीं कर रहे हैं। अब सरकार क्या कर सकती है?

हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह मामला पक्ष या विपक्ष का है। यह मामला पूरे देश का है। इसलिए इस मामले पर सभी दलों के नेताओं की बात होनी चाहिए। सभी दल के नेताओं से इस पर सुझाव लेना चाहिए। सभी नेताओं को जानकारीयां हैं। अपने साथियों के ग्रुप बनाकर नेता सदन उनसे मिलें। आप प्रदेश के लोगों से मिलें कि प्रदेश का क्या हाल है? उनके नेता भी आएँ, भले ही पूरे शासन

को मत बुलाइए। यह देश का सवाल है, सत्तापक्ष या विपक्ष का नहीं है।

महोदया, हम मानते हैं कि यह दैवीय आपदा है, लेकिन दैवीय आपदा का बहाना सरकार नहीं ढूँढ सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी कैसे दिया जाए, अन्न कैसे पैदा कराया जाए, पानी सिंचित कैसे किया जाए? केवल दैवीय आपदा के नाम पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे वह पाताल से पानी ले, चाहे कहीं से पानी ले, चाहे बांध बनाए, चाहे समुद्र से पानी ले, लेकिन यह सरकार का काम है। कोई यह कहता है कि दैवीय आपदा है, लेकिन सरकार यह नहीं कह सकती, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती।

अध्यक्ष महोदया, यह गंभीर सवाल है, आप इस पर चर्चा करायें। यह एक या दो घंटे की चर्चा नहीं है, इस पर पूरे दिन सदन में चर्चा हो। आज अकाल की स्थिति है। खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है और आगे आने वाली फसल के लिए इंतजाम नहीं है, तो भुखमरी फैलेगी, क्योंकि अन्न नहीं है। क्या हम विदेशी अन्न पर ज़िंदा रहेंगे? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर पैदावार किसी ने बढ़ायी है, तो किसान ने अपनी मेहनत और बुद्धि से बढ़ायी है। सरकार ने कोई ज्यादा मदद नहीं की है। यहां किसान भी बैठे हैं। ऐसे-ऐसे गांव बता देंगे जो आज पैदावार बढ़ा रहे हैं। उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। किसान ने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से ढाई गुना पैदावार बढ़ाई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसानों को प्राथमिकता के आधार पर, गांवों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। शहरों में भी संकट है लेकिन यहां इंजीनियर रहते हैं, एमपी रहते हैं, एमएलए रहते हैं, मंत्री रहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, प्रधान मंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं और सारे अधिकारी रहते हैं। यहां तो हाहाकार हो जाएगा। यहां पीने के पानी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन सुदूर इलाके जहां गांव हैं, देहात हैं, आदिवासी हैं, गंदा पानी है, उनके लिए क्या इंतजाम होगा। दिल्ली की क्या चिन्ता है, दिल्ली में इंतजाम हो जाएगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : एक दिन सांसद खड़े होकर कहेंगे कि पानी नहीं है, पानी नहीं है।...(व्यवधान) पानी मैला हो गया था।...(व्यवधान) पानी गंदा है। पानी की बोतलें बिक रही हैं। एक बाल्टी पानी की क्या कीमत हो गई है। आज यह हालत है। इसलिए आपको कोई न कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। आप आज ही अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुला लें, कुछ भी कर लें, हमारे सुझाव आ चुके हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर जरूरत समझें तो नेताओं को बुला लें, लेकिन जरूरत नहीं है। आपको काम करना है, सुझाव आ गए हैं, आप जानते हैं।...(व्यवधान) आपने मुझे इतना बोलने देने की कृपा की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस गंभीर सवाल पर पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त रहिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है जिसे सम्मानित सदस्य श्री यादव ने विस्तार से यहां रखा है। यह दैविक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। आज पूरे देश के किसान और नौजवान सब परेशान हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है कि किसी के नाते आपदा आई है, लेकिन संयोग है कि यूपीए सरकार बनते ही यह देश अकाल की गिरफ्त में आ गया है।...(व्यवधान)

सही क्या है, यह बता दीजिए।...(व्यवधान) आप पहले बात सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ।...(व्यवधान) सरकारें बनती, बिगड़ती रहती हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मैंने कहा यह संयोग ही है, इसमें आपका दोष नहीं है। यह संयोग है कि आपकी सरकार बनते ही पूरा देश अकाल की चपेट में आ गया है।...(व्यवधान) किसान जो इस देश की रीढ़ है, आज सबसे ज्यादा परेशान है। पशु-पक्षी से लेकर इंसान, पहाड़ी इलाके, पूरे देश में जहां शुद्ध पानी नहीं मिलता था, सूखे की हालत यह है कि दिल्ली में पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है। लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं जिससे आने वाले दिनों में गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। पानी के अभाव में देश में बिजली का सबसे बड़ा संकट है। पन बिजली परियोजना जो पानी की वजह से चलती थी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त हो जाइए। आप इस तरफ देखकर संबोधित कीजिए।

â€(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : आपने अपनी बात कह दी है, अब चुप रहिए।... (व्यवधान)

मैं समझता हूँ कि सारे दल के नेताओं, प्रदेश सरकारों, मुख्य मंत्रियों और संबंधित मंत्रियों को बुलाकर, सदन के सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, विद्वान हैं, सारी स्थिति से परिचित हैं, सदन के नेता इस गंभीर संकट को देखते हुए प्रदेश सरकारों से राय लेकर, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है, जो जमीनी हकीकत है, पार्लियामेंट के सारे सदस्य हलके से चुनकर आते हैं, वे इस गंभीर स्थिति से निपटना जानते हैं और सच्चाई भी समझते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी राय भी ली जाए। देश में अकाल, सूखे की वजह से जो गंभीर स्थिति पैदा हुई है, उस पर गंभीरता से विचार किया जाए।

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, I thank you for allowing me to speak on this subject. Madam, while associating with the feelings of the other Members of the House, I would say that Tamil Nadu is facing a grave problem. Usually, water from the Mettur Dam across Cauvery will be released for irrigation on 12th of June of every year. But this year, water has not been released so far because there is no water in Mettur Dam. The farmers of the delta region are suffering because of this.

Madam, Tamil Nadu is situated at the end of this country. Normally, it is an accepted rule internationally that lower riparian areas should not be denied water by the upper riparian States. But here, Tamil Nadu is facing problems and water is not released for the State. Hence our farmers are suffering for want of water. One year's impact will continue for the next two or three years. That is the issue. If there is water shortage for one year, the impact will continue for the next two to three years. The Government should intervene, have discussions with the Chief Ministers of all the States particularly Tamil Nadu and see that some redressal measures are taken.

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, आज देश में सूखे की बड़ी गंभीर स्थिति है। पहले जब सूखा पड़ता था, तो वह एक-दो सूबे या राज्य में ही पड़ता था, लेकिन इस बार सूखे की चपेट में पूरा देश है। ऐसा कोई सूबा या राज्य नहीं है, जहां सूखे का प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारा कहना है कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है।

अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे देश की 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इस बार किसान ने अपने खेतों में जो बीज बोया था, वह सब सूख गया, जल गया। उनके पास बोने के लिए दोबारा बीज नहीं है। हमारे देश में 50-60 फीसदी से ज्यादा प्रांतीय, मार्जिनल और गरीब किसान हैं, जो अपने पास केवल एक बार के लिए ही बीज रखते हैं। आज उनके पास बीज बोने के लिए नहीं हैं।

आज देश में ऐसी परिस्थिति है कि अगर सरकार उनकी मदद नहीं करती, तो देश में इस बार फसल नहीं होगी। यदि देश में अभी भी बारिश होती है तब भी फसल नहीं हो सकती। यदि सरकार समय पर उनकी मदद नहीं करती, तो हमारा उत्पादन घट जायेगा।

दूसरी, हमारी सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। इस बार हमने चुनाव में भी देखा है कि जनता की एक ही मांग थी -- पानी। उनका कहना था कि हमें पानी दो। देश में पीने के पानी का संकट हो गया है खासकर गांवों में। शहरों में कहीं न कहीं पीने के पानी का विकल्प है, लेकिन गांवों में पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट है। वहां लोग ट्यूब वेल और कुओं पर निर्भर करते हैं। ट्यूब वेल में पानी का लैवल काफी नीचे चला गया है। वहां कुएं आदि सब सूख गये हैं।

इस कारण से आज गांवों में बीमारियां फैल रही हैं, गांव में लोगों को डायरिया हो रहा है, मौत हो रही है। यह भी बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने है। इसे भी हमें देखना होगा। इस सदन में चर्चा होगी, दिन भर चर्चा होगी, स्ट्रक्चर्ड डिबेट होगी, लेकिन डिबेट से समस्या हल नहीं होगी, हल निकालना होगा। एक शॉर्ट टर्म और लॉग टर्म प्लान हमें बनाना होगा कि अगर भविष्य में हमारे देश में ऐसी समस्या होगी तो उसका सामना कैसे करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए डा. स्वामीनाथन ने सुझाव दिया है, हमारे देश के कृषि विज्ञानियों के साथ सलाह-परामर्श करके, तमाम मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग बुलाकर और सभी पोलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करके, केन्द्रीय सरकार को एक कंटीजेन्सी प्लान बनाना होगा कि कैसे हम इसका समाधान कर सकेंगे, कैसे इसका मुकाबला कर सकेंगे। हमारे देश में 80 फीसदी आबादी आज इस संकट में फंसी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : इस संकट का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए राज्य सरकारों की मदद करनी होगी, किसानों की मदद करनी पड़ेगी। हर सामान का भाव बढ़ रहा है।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What Shri B. Mahtab says only will go on record.

(Interruptions) *â€

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Madam, for allowing this discussion to be held in the House. As we all know, drought is a serious problem and it is treated as slow death. People who are affected by drought seldom come on to the streets. The devastation that is caused by drought is seldom seen by naked eye in comparison to the devastation that is caused by cyclone or by flood. So, drought is a problem which affects the farmers at large and the weaker section of the society at the most. So, when such issue has been raised in this House, knowing the sense of the House, Madam, you have very rightly accepted the suggestion of our leaders and have allowed a number of Members to participate in this burning issue today.

I come from a State in which there was no rain for the last ten months. A coastal State in the eastern part of this country, Orissa had not witnessed rain for ten months. But when the rain came hardly ten days back, for the last seven days Orissa is facing flood. When this House is deliberating on drought I am forced to draw the attention of the Government and this House to the calamity that has come upon us because of flood. The banks of river Baitarani have been breached. Large parts of Bhadrak and Jajpur Districts have been inundated. In the lower reach of Hirakud reservoir we have had a big cloud burst and the lower region of Mahanadi is facing heavy flood. Similarly, in the southern part of Orissa, in Rushikulya area of Ganjam District also flood situation prevails. An accident has taken place in Nayagarh District where a bus was washed away and casualties have taken place.

Madam, I have certain suggestion for the Government to consider. Already in Orissa the crop of highland variety of paddy has totally been destroyed. The crop of lowland variety of paddy has totally been destroyed because of heavy flood. I would draw the attention of the Government to extend full support to the State of Orissa. To help the farmers, a specific package be prepared to meet the challenge that the climate has posed to us.

The dichotomy today is that most of the reservoirs in Orissa State are not yet full, but we are facing flood. Reservoirs like Hirakud, Indiravati, Rengali, Upper Kolab, Chittrakunda and Badnalla are not full, but large parts of the area are under water. ... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI B. MAHTAB : I have only a few suggestions to make. I will just take a minute.

For the short-term variety paddy, the time is already over. Khariff crop is in jeopardy; the farmers are in distress. The Central Government should prepare an action plan; preparation should be made for providing jobs to check migration; health programmes must be made at the most; rural development should prepare a special contingency plan to help rural folk; and lastly, sufficient seeds should be provided for Rabi crop. With these suggestions, I conclude. Thank you.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, लगभग पूरे देश में आज सूखे की स्थिति है। मैं सबसे पहले सदन की ओर से आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि वह जल्द से जल्द सूखा घोषित करे। मैं आपके माध्यम से एक और मांग सदन में रखना चाहता हूँ। एनडीए सरकार के समय उस समय के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया था और उस पर काम शुरू किया था। लेकिन पिछली यूपीए सरकार ने उसे बंद बस्ते में डाल दिया, उसे वाइंड अप कर दिया। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नदियों को जोड़ने वाले उस प्रकल्प को बंद बस्ते से निकाल कर उस पर पुनर्विचार करे।

अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में सूखे की स्थिति है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी गोपीनाथ मुंडे जी ने भी कहा कि टैंकों से पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां टैंकों के लिए भी पानी नहीं है, क्योंकि नदियां और कुएं सूख गए हैं, जहां से पानी लेकर उनसे सप्लाई होती थी। इसलिए टैंकों से भी पानी पहुंचाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति आज महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में खासकर पैदा हो गई है।

कुदरत का भी अजीब करिश्मा है। जब पूरे देश में सूखा है, तो मुम्बई में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। हमारे कोंकण क्षेत्र में रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बाढ़ आ गई है। इसके अलावा पुणे का कुछ हिस्सा और नासिक जिले में भी बाढ़ की स्थिति है। देश में जो सूखे की स्थिति है, उससे सरकार को लड़ना है। देश के कुछ ऐसे हलके हैं, कुछ ऐसे सूबे हैं, जहां बाढ़ की स्थिति का सामना करने की नौबत आ गई है। प्रकृति का अजब करिश्मा हमें दिखाई दे रहा है कि एक जगह बाढ़ है तो दूसरी जगह सूखा है। शरद यादव जी ने अभी एक सुझाव दिया था कि जिन राज्यों में पानी है, वर्षा हो रही है, वहां पर यदि अच्छी फसल लेनी है तो सरकार को उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मेरे क्षेत्र यानि कोंकण एरिया में, पुणे तथा नासिक में बारिश हो रही है, वहां पर समय पर खाद मिलनी चाहिए। इसके अलावा सूखे के कारण वहां जो पहले बीज बोया गया था, वह जल गया है। इसलिए उसे दोबारा बोने की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि खरीफ की फसल, यदि भविष्य में बारिश होती भी है, तब भी वह इस साल की देश में खत्म हो जाएगी। इस तरह यह मानकर चलें कि हमारी खरीफ की पूरी फसल खत्म हो चुकी है। इसलिए सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : शरद यादव जी ने प्रश्न काल में जिस विषय को उठाने की कोशिश की और आपने बाद में उस पर चर्चा कराने की अनुमति दी, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज पूरे देश के सामने अकाल और सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह तुरंत देश में सूखे की घोषणा करे।

MADAM SPEAKER: Shri Sudip Bandyopadhyay, I had called your name but you were not present.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I was not aware.

MADAM SPEAKER: But you have sent your name. Are you speaking now?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Yes, Madam, I am speaking.

Madam, farmers are affected either by drought or by flood. It is a common phenomenon. No doubt, the Government of India and the hon. Finance Minister in his Budget Speech has ventilated his ideas to protect the interest of the farmers at the grass-root level on a large scale. Sometimes, we are affected by drought or by floods. Sometimes, devastating storms affect us in the name of Tsunami or tornado or Aila. We are all affected by different kinds of natural calamities. But humanbeings cannot fight natural calamities on their own will or with their own interest. If you are willing to fight drought situation in the country, water conservation process is to be introduced at the district level or at least at the State level. This idea has to be floated. This process of conservation of water system should be announced as a policy of the Government of India so that at least the agricultural people who are really connected with the grass-root level can be benefited on a large scale.

Madam, in our State, Aila affected many areas. The Government of India has allotted Rs.1000 crore. In this connection, we will also request the Government to make a monitoring system for the amount which has been sent to see that it is properly spent. It should be taken care of that this fund is not diverted for other purposes of the State Government.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, all our Members are concerned about the drought condition prevailing in this country. This situation is prevailing in my State of Tamil Nadu also and because of this drought condition, most of the reservoirs in Tamil Nadu have dried up. With the result, the farmers are not in a position to do agricultural activities. The farmers who started some kind of agricultural activities are now severely affected. There is acute shortage of drinking water in our State of Tamil Nadu. Whenever I travel in the State, most of the people of my Constituency request me for providing drinking water and they are blocking us. They ask us as to what are we doing as representatives of the people in this august House. They say that you should try to persuade the Government to see that drinking water is provided to all the citizens of this country. That is their demand. This is the high time that we have to think how to provide drinking water. Tamil Nadu is depending only on Cauvery water. All the drinking water projects are connected with the Cauvery water. So, if we are not able to get water from Cauvery, we would not have even the drinking water. In most of the cities of my Constituency, drinking water is being provided once in 15 days or 20 days. So, we are not able to get water. Therefore, I would request this Government to direct the Karnataka Government to release some water from Kabini and Krishna Rajasagar into Cauvery. This will help us not only in regard to drinking water but for agricultural operations also. We have to do this for Thanjavur and other delta areas.

Madam, Andhra Pradesh has started illegal construction of dam on Palar river. It would adversely affect T.N.. Therefore, I would request the Central Government to intervene and direct the govt of Andhra Pradesh to stop the construction of dam on Palar river.

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): मैडम, पूरे देश के लिए परिस्थिति बहुत गंभीर है। यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए परिस्थिति बहुत गंभीर है। इस गंभीर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए, सरकार की तरफ से, जल्दी के जल्दी, कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि इस परिस्थिति को नेशनल कैलेमिटी घोषित किया जाए और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग हम करते हैं कि देश के सभी राज्यों को साथ लेकर, केन्द्र सरकार एक जाइंट-प्लान, परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए बनाए।

Madam, Speaker, let me give a few statistics. In the month of June the rainfall has been only 52 per cent of the total normal rainfall. It is much below normal. Only 30 mm rain was recorded in the month of June. Sowing of paddy is down by 25 per cent in the whole of the country. This fall is not merely restricted to States like Tamil Nadu, Kerala and Uttar Pradesh. The

production of oil seeds is down by 45 per cent. इसका कारण यह है कि महंगाई बढ़ रही है।

There is an abnormal increase in the prices of essential commodities, particularly the agricultural produce like vegetables. The traders and wholesalers anticipating drought are increasing the prices of essential commodities. Also, anticipating drought, a terrible speculation is going on in the country. इन परिस्थितियों को देखते हुए, हम चाहते हैं कि सरकार संसद को बताए कि वह क्या करने जा रही है? हम इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मेट्रोलाजिकल विभाग से मीटिंग की है। हम यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आफिस ऊर्जा विभाग से बात कर रहा है कि हिन्दुस्तान में बिजली का उत्पादन इतना कम क्यों हो रहा है? लेकिन जो भी हो रहा है, वह कैबिनेट में हो रहा है, वह साउथ ब्लॉक और नार्थ ब्लॉक के बीच हो रहा है। इस सबसे पार्लियामेंट अंधेरे में है। What is happening in the Government is happening within the precincts of the North Block and the South Block. The Parliament has been kept in dark. Therefore, I am suggesting that it should be declared a national calamity; I am suggesting that there should be a meeting with the Chief Ministers of the States; I am suggesting a meeting with experts to discuss the possibilities of dry cultivation and also I am suggesting that Parliament should be made aware of what the Government is thinking to deal with a national catastrophe that has overtaken the country.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदया, आज देश में जो अकाल की स्थिति बनी है, उसके ऊपर सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। हमने बजट को देखा है और हमें लगता है कि सूखे की स्थिति को देखते हुए, सरकार ने कोई भी पैकेज किसान के लिए नहीं दिया है। अकाल की वजह से कृषि, पीने के पानी और बिजली की समस्या होने वाली है। पिछले पांच साल से पहले 65 मिलियन टन फूड रिजर्व था, लेकिन अब वह 20 मिलियन पर आ गया है। 20 मिलियन फूड रिजर्व अकाल में पूरे देश के गरीब आदमी के लिए खाना देने के लिए है, उसी तरह से फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सीरियसली सोचना चाहिए। इसके लिए इमिडिएट एक्शन प्लान होना चाहिए। इसके अलावा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर प्लानिंग की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक लॉग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए। देश की नदियों के पानी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। रिवर लिंकिंग के लिए आने वाले अच्छे सुझावों पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। रिवर लिंकिंग का भी लॉग टर्म प्लान होना चाहिए। इसी प्रकार से स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले साल का गेहूँ का जो इनपुट कॉस्ट सरकार ने वर्क-आउट किया है, वह 421 रुपया है। वर्क आउट करने के बाद अभी कहा जा रहा है कि 1080 रुपया गेहूँ का रेट दिया गया है। क्या कोई भी किसान पचास प्रतिशत लाभ में है? इस तरह से गलत इनपुट कॉस्ट...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : मैडम, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। किसान पर अन्याय हो रहा है। आंध्र प्रदेश पर अन्याय हो रहा है। उसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, माननीय शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, गीते जी और आचार्य जी ने जो चर्चा में भाग लिया, उन्होंने जो अपने उद्गार व्यक्त किये, जो चिंता व्यक्त की, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूँ। मैंने शुरू में ही जनरल बजट की चर्चा के दौरान आगाह किया था कि सूखे का अकाल का भारी संकट आ गया है और सरकार ने जो बजट तैयार किया है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह आम आदमी के लिए बिल्कुल चरमरा जाएगा।...(व्यवधान) मैं जानता हूँ कि आपके पास समय का अभाव है। बहुत लोग बोलने वाले हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि सभी पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं को, सभी राज्य के मुख्य मंत्रियों को और जो कृषि विशेषज्ञ लोग हैं, उनको और हर राज्य के जो किसान हैं, वास्तव में जिनको अनुभव है, जो किसान नेता कम लेकिन जो आम किसान हैं, उनको ज्यादा जानकारी है कि किस सैगमेंट में, किस राज्य में क्या होने वाला है? इसलिए उनको भी बुला लीजिए। अलग से भी उनको आप बुला सकते हैं।

महोदया, यह जो ग्लोबलाइजेशन हुआ और दुनिया में जब हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में प्रवेश किया, तो जो पुराना सीड था, यह सब समाप्त कर दिया गया। मोटा अन्न, डा. लोहिया जी कहा करते थे, कि मरुआ रागी जिसे कहते हैं, मरुआ कम पानी में भी गर्मी में भी घूड़ा मार कर भी लाठी से मरुआ लगा देते थे,...(व्यवधान) सूखे की बात हो रही है, इसलिए जो साठी धान था, सांवा था, पूदो था, "साठी होकर साठ दिन और वर्षा होकर रात दिन।" वर्षा तो है नहीं, इसलिए ओजोन में जो भारी छेद हो गया है, यह जो लेयर पर लेयर, यह जो ग्लोबल वार्मिंग है,...(व्यवधान) अंग्रेजी हम भी जानते हैं,।...(व्यवधान) इसलिए यह भी हमें देखना चाहिए कि कहीं इसका असर तो देश पर नहीं पड़ रहा है। यह भी हमें देखना पड़ेगा। घोर कल्युग तो आ ही गया है। जब पाप बढ़ता है तो प्रलय होती है और जब सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण करने में फेल हो जाती है तो मालथस थ्योरी लागू होती है। प्रकृति अपना काम करती है।...(व्यवधान) इसमें आप मीटिंग बुला लीजिए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए। सिर्फ सरकार की ही नहीं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हर पोलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। भूखा किसान, मजदूर और फटेहाल खेत और खलिहान होगा तो राज्य सरकार और देश की सरकार के खिलाफ आक्रोश उठेगा।

13.00 hrs.

जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी नहीं छट पाएंगे, चाहे वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। सब जगह मारकाट शुरू हो जाएगी, लोग पत्थर

फेंकेगे और कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये लोग आराम से हैं और हम भूखे मर रहे हैं। पानी, तो अब पानी भी नहीं है, देश में पानी के लिए तो मारकाट होने वाली है, पानी के लिए ऐसा होता ही है। इन चीजों को सबसे पहले सब काम छोड़ कर कीजिए। यह राष्ट्र का सवाल है, सबका सवाल है। आपके पास सरकार है, पावर है, साधन है, शक्ति है इसलिए आपको पहल करनी चाहिए।

मैंने सुझाव दिया था कि एक्सपोर्ट को तुरंत रुकवा दीजिए। गेहूं, चावल, दाल, खाद्य पदार्थ, मांस, मछली देश से बाहर भेज रहे हैं तो इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है नहीं तो ऐसा बड़ा संकट आएगा कि हर इलाके में हर रात डाका पड़ेगा, भूखे लोग रात भर लूटपाट करेंगे। भूखा आदमी और कर ही क्या सकता है?...(व्यवधान) जानवर के चारा की बात आई है, जब जानवर ही मर गया, मर रहा है।...(व्यवधान) रंजन जी, मैं आपका इशारा जानता हूं। आप ज्यादा काबिल मत बनें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

â€(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : यह भारत की जनता भी जानती है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप इधर संबोधित कीजिए।

â€(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आज बड़े पैमाने पर सूखे की स्थिति हो गई है, अकाल की स्थिति हो गई है। इसलिए इसकी आज नहीं तो कल घोषणा कीजिए। हम सब लोगों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। यह सवाल सिर्फ किसान का नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है। अगर हम मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे तो हर परिवार, हर वर्ग, हर तबका, खेत खलिहान से लेकर इंडस्ट्री तक प्रभावित होगा, केवल किसान ही नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि जल्दी बैठक बुलाइए और निर्यात तुरंत बंद कीजिए। यह बात सही है कि आलू का दाम 16 रुपए किलो हो गया है, तुअर दाल 90 रुपए किलो हो गई है जबकि यह दाल जल्दी गलती ही नहीं है। इस सब चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज यहां जो चर्चा चल रही है, यह स्थिति सचमुच बहुत गंभीर है। पूरे देश को इसकी चिंता है। जैसा कि हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा है कहीं पर बरसात है तो कहीं सूखा। मैं सूखे के हालात को समझती हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव में सूखे के हालात को देखकर रौने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। वहां की औरतों की दशा बहुत खराब है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई ऐसे ब्लाक्स हैं जिन्हें ब्लैक ब्लाक्स डिकलेयर कर दिया गया है क्योंकि पानी का स्तर ढाई सौ मीटर से नीचे हो गया है और बोरिंग तक होने की कोई संभावना नहीं है। सूखे की स्थिति केवल हमारे देश की नहीं है। कहीं ठंडा, कहीं गरम, कहीं बरसात, कहीं सूखा है। जैसा कि लालू जी ने भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ा मुद्दा है। यहां इस पर चर्चा करने में बहुत समय लगेगा इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। शायद आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 18-23 मीटर प्रति वर्ष हिमालयन ग्लेशियर पिघलता जा रहा है। आज देश में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है यह सिर्फ किसी सरकार की वजह से नहीं है। इसका दायित्व भी हमारा ही है। हम लोगों की वजह से, मनुष्य जाति की वजह से यह हुआ है। आज इसका दायित्व 543 सदस्य, जो यहां मौजूद हैं, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने आए हैं, उनका है। मेरे ख्याल से सरकार के बारे में बोलना और यह कहना कि हम बैठक कर लें, इन सबके अलावा हम सबका अपनी कांस्टीट्यूंसी में एक दायित्व बनता है।

इलैक्शन लड़ने के लिए हम लोग रात-दिन गांव-गांव घूमते हैं। लेकिन इस वक्त हम यहां क्यों बैठे हुए हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? यहां हमारी सरकार है और सरकार चर्चा करके हमें पैकेज बताये कि हमें क्या करना है और सरकार हमें बतायेगी कि हमें क्या करना है। वहां जाकर हम काम करेंगे। ...(व्यवधान) जो परेशानी है, अगर मैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये

â€(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Munde, you have had your turn.

...(Interruptions)

MADAM SPEAKER: I have called Dr. Rattan Singh Ajnala.

...(Interruptions)

श्रीमती अन्नू टण्डन : मैं अपने सभी सीनियर लीडर्स को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूं।...(व्यवधान) मुझे बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डा.रतन सिंह अजनाला।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्रीमती अन्नू टण्डन : एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए...(व्यवधान) आप मुझे बोलने तो दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डा.रतन सिंह अजनाला, आप बोलिये।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : यहां पर हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, वह सब इस बात को जानते हैं कि स्थिति गंभीर है। लेकिन स्थिति गंभीर है, स्थिति गंभीर है, बोलने से क्या होगा। हमें मालूम है कि हमारी सरकार भी इसके लिए कुछ कर रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डा. रतन सिंह अजनाला की बात ही रिकार्ड में जायेगी और कुछ रिकार्ड में नहीं जायेगा। डा. रतन सिंह अजनाला, आप बोलिये।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : आप यह कह रहे हैं कि मुख्य मंत्रियों को यहां बुलाया जाए और इस विषय पर चर्चा की जाए। हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को यहां आने का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें न तो पार्को से फुर्सत है और न मूर्तियों से फुर्सत है।...(व्यवधान) अमेठी में जब आम जनता बिजली के लिए धरना देती है तो पुलिस से कहकर उन्हें घरों से बाहर निकाल-निकाल कर मारा जाता है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Munde, you have had your turn. You please sit down.

...(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shrimati Annu Tandon, please conclude.

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको बोलना है, आप बोलिये।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैडम, आप हाउस साइने-डाई एडजर्न करा दे, हम सब क्षेत्र में चले जायेंगे। ...(व्यवधान) इस सदन में कोई नहीं बैठेगा। यह सदन चर्चा के लिए बना है। हम लोगों की भावनाएं बोल रहे थे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सिर्फ डा. अजनाला की बात रिकार्ड में जायेगी।

...(व्यवधान) *

MADAM SPEAKER: Other hon. Members who want to associate may send their names to the Table of the House.

...(Interruptions)

Now, we have to take item number 7 – Shrimati Preneet Kaur.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये।

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : जब हम आपको कह रहे थे तो आप नहीं बोले। अभी आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए। मैं आपको अभी बुलाती हूँ। आप एक मिनट बैठिये। मैं आपको बुलाती हूँ। अभी आप बैठिये।

अध्यक्ष महोदया : हम बुला रहे हैं। जब हमने बुलाया था तो वह नहीं बोले। डा.रतन सिंह अजनाला, अब आप बोलिये।

...(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Dr. Ajnala, I have just called you.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदया :

सर्वश्री घनश्याम अनुरागी,

शैलेन्द्र कुमार,

रामकिशुन,

आर.के.सिंह पटेल,

डा.रामचंद्र डोम,

जे.एम.आरुन रशीद,

श्रीमती जयाप्रदा,

श्रीमती सुस्मिता बाउरी,

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी के नाम श्री शरद यादव द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध किये जाते हैं।

*Dr.RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) Madam Speaker, Thank you very much for allowing me to speak on this very serious issue relating to the farmers of the whole country as referred to by Hon'ble Member Shri Sharad Yadav ji. I am surprised to hear the views of Congress Party's lady member who said that this issue is not required to be raised in this House. I think she has been elected to this House for the first time and she does not know what to speak and what not to speak.

अध्यक्ष महोदया : आप विषय पर बोलिए। जो आपका विषय है, आप उस पर बोलिए।

डा. रतन सिंह अजनाला : पहले आकर सीखना चाहिए, फिर बोलना चाहिए।

अध्यक्षा महोदय : जो आपका विषय है, आप उस पर बोलिए।

*Dr.RATTAN SINGH AJNALA She should learn first and then speak.

अध्यक्ष महोदय : डा. अजनाला, अगर आपको पंजाबी में बोलना था, तो आप पहले नोटिस देते। आगे से इसका ध्यान रखिए।

*Dr.RATTAN SINGH AJNALA : As far as Punjab state is concerned it is also in the grip of drought for the first time. The water level of Bhakhra Nangal Dam has come down by 40% and in Ranjit Sagar Dam the water level has come down to 116 meter. The water level of various canals in Punjab has also come down by 50%. We are facing this problem because of these dams also. And also done to delayed onset of Monsoon. Due to this we are facing severe power crisis in the state. Madam Speaker, you would be surprised to know that we have curtailed the working hours in our offices and schools because power shortage. We have also stopped power supply to the industries in the state so that power could be made available to the farmers of Punjab. We have purchased electricity worth Rs.1200 crores for supplying it to the farmers of the state.

अध्यक्ष महोदय : आपको नोटिस देना पड़ेगा। नियम यह है कि आप पहले नोटिस दीजिए।

*Dr.RATTAN SINGH AJNALA : Madam please note it forever that I will always speak in Punjabi only and there is no second opinion about it. I have been speaking in Punjabi for years together.

Madam, This Congress Government has increased the price of diesel by Rs.2/-. The cost of agricultural input has increased by Rs.500-600 per acre due to increase in the price of diesel and power. Madam Speaker, the Hon'ble Minister is sitting here. I would like to make a request that as every state has its own specific requirements and problems the conference of Chief Ministers should be convened and they should discuss and decide about the requirements of each state which should also be met so that the people in this country could get two square meals a day. This is a very serious matter.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.10 p.m.